बब्बर खालसा का आतंकी लजर मसीह कौशंबी जिले में पकड़ा गया

कौशांबी, 06 मार्च। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पैशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कौशांबी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक कथित सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी की पहचान पंजाब के अमृतसर के रामदास क्षेत्र के कुर्लियान गांव के रहने वाले संदिग्ध आतंकी लजर मसीह के रूप में हुई है। आतंकी की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है कि आंतकी लजर हाल ही में संपन्न हुए प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी घटना करने की फिराक में था।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने गिरफ्तार आतंकी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि आतंकी लजर लगातार पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के साथ सम्पर्क में था। पाकिस्तान में बैठे कुछ हैंडलर उसे लगातार ड्रोन से गोला बारूद और असला भी भेज रहे थे। प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि लजर यूपी के प्रयागराज जिले में संपन्न हुए महाकुंभ में कोई बड़ी आतंकी घटना करना चाहता था। इसके बाद वो पुर्तगाल भागने की फिराक में था।

विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा में चूक को ब्रिटेन ने गंभीर माना

जयशंकर लंदन के चैथम हाउस से जब बाहर निकल रहे थे, तब एक व्यक्ति ने दौड़कर पुलिस के सामने, भारतीय ध्वज फाड़ा था

- **ब्रिटेन ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों को बाधित करने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है।**

लंदन, 06 मार्च। जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक मामले पर भारत की कड़ी आपत्ति को यूके ने भी गंभीरता से लिया है। ब्रिटेन ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक अस्वीकार्य है। यूके ने अपने बयान में कहा है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए तेजी से काम किया। "हम अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप अपने सभी राजनयिक आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षा बाधित करने के इस तरह के प्रयासों की हम कड़ी निंदा करते हैं।"

ज्ञातव्य है कि एस जयशंकर बुधवार को लंदन के चैथम हाउस में चर्चा के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी कार की ओर दौड़ा और पुलिस अधिकारियों के सामने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फाड़ दिया। ब्रिटेन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, जिसमें खालिस्तानी चरमपंथियों के एक समूह ने लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा को बाधित करने का प्रयास किया। इस सुरक्षा उल्लंघन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और इस मामले में ब्रिटिश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों को बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। गुरुवार को जारी कार्यालय के बयान में कहा गया, "हम विदेश मंत्री की यूके यात्रा के दौरान कल चैथम हाउस के बाहर हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि यूके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों को डराने, धमकाने या बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

"घटना के संबंध में यूके की यह प्रतिक्रिया भारत सरकार द्वारा सुरक्षा उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने और "भड़काऊ गतिविधियों" की निंदा करने के कुछ घंटों बाद आई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में "अलगाववादियों और चरमपंथियों" के छोटे समूह द्वारा "लोकतांत्रिक स्वतंत्रता" के दुरुपयोग की निंदा की और यूके के लिए एक सख्त संदेश भी जारी किया था।

आबू रोड के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैड कांस्टेबल विनोद लाम्बा ने बताया कि मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए कार के दरवाजे तोड़े गए। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला जा सका।

सड़क हादसे में मारे गए सभी लोग जालोर जिले के निवासी और और प्रजापत समाज से हैं। हादसे में एक परिवार के नारायण प्रजापत (58) पुत्र नरसाराम, उनकी पत्नी पोशी देवी (55) व उनका पुत्र दुष्यंत (24) निवासी कुम्हारों का वास, जालोर, सहित, चालक कालूराम (40) पुत्र प्रकाश चांदराई जालोर , यशराम (4) पुत्र कालूराम चांदराई जयदीप पुत्र पुखराज प्रजापत शामिल हैं। दरिया देवी (35) पत्नी पुखराज निवासी जालोर, घायल हैं, जिन्हें आबूरोड राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही रैफर किया गया। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई।

जिला कलैक्टर अल्पा चौधरी, एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने घटना पर दुःख जताया व घटना के बारे में आवश्यक जानकारी ली। शाम को जालोर निवासी नारायण सहित अन्य का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गयाा।

पूरे परिवार की अर्थियां जब एक साथ उठीं तो हर किसी के आंखों में आंसू नजर आए।

'हजारों भारतीय युवाओं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिकन आप्रवासन (इमिग्रेशन) व्यवस्था में बैकलॉग की स्थिति यह है कि अनेक लोगों को स्थायी नागरिकता के लिये लम्बी प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ आवेदनों में तो 12 से 100 वर्ष तक प्रतीक्षा करना सम्भावित बताया गया।

टैक्सस की एक अदालत के हाल ही के एक फैसले के अनुसार, डैफर्ड एक्शन फॉर चिल्ड्रन अराइवल्स (डीएसीए) प्रोग्राम के तहत, नये आवेदकों के लिये वर्क परमिट ब्लॉक कर दिये गये हैं। इस फैसले से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। डीएसीए, अनडॉक्यूमेन्टेड युवाओं को डिपोर्टेशन से दो साल अस्थाई संरक्षण प्रदान करता है, जिसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है, इनमें वे युवा भी शामिल है, जिनका, 21 वर्ष की उम्र के बाद, डिपेन्डेन्ट स्टेटस समाप्त हो चुका है। इस प्रावधान के बिना, बहुत से भारतीय युवाओं को अनिश्चित भविष्य का डर सता रहा है।

यू.एस. सीनेटर बर्नी सैन्डर्स, जो एक अग्रणी प्रगतिशील नेता हैं, ने इस साल के शुरु में एच-वन बी वीसा प्रोग्राम की आलोचना की थी तथा यह तर्क दिया था कि यह प्रोग्राम मुख्यतः कॉर्पोरेशन्स के लिये लाभदायक है क्योंकि वे अमेरिकनों को काम पर रखने के बजाय, कम वेतन वाले विदेशी कामगारों को लेते हैं।

सैन्डर्स ने कहा था, "एच-वन बी प्रोग्राम का मुख्य काम "सर्वोत्तम तथा कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों को नौकरी देना नहीं, बल्कि अच्छा वेतन मांगने वाले अमेरिकनों के स्थान पर, कम वेतन स्वीकार करने वाले बाहरी देशों के हजारों लोगों को नौकरी पर रखना है। इन लोगों के साथ अनुबन्धित कर्मचारियों की तरह व्यवहार किया जाता है।"

सैन्डर्स ने लेकन रिले एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसका उद्देश्य एच-वन बी वीसा फीस को दुगुना करना था, ताकि अमेरिकन 370 मिलियन डालर प्रतिवर्ष अर्जित कर सके तथा एसटीईएम फील्ड में अमेरिकन छात्रों को करीब 20,0000 छात्रवृत्तियाँ दे सके। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया था कि एच-वन बी वर्कर्स वेतन बढ़ाकर, कम से कम औसत स्थानीय वेतन के बराबर कर देना चाहिये, जिससे कम्पनियों को अमेरिकन वेतन में कटौती से रोका जा सके। सैन्डर्स चाहते थे कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क तथा भारतीय अमेरिकन उद्यमी विवेक रामास्वामी जैसे अरबपति एच-वन बी प्रोग्रैम में आर्थिक सहयोग दें।

उन्होंने कहा, "दुनिया के सबसे अधिक धनवान, एलन मस्क तथा अन्य-खरबपति जोर देते हुये कहते हैं कि अत्यधिक कुशल वर्कर्स की कमी के कारण, एच-वन बी प्रौग्रैम बहुत उपयोगी हो गया है। मेरी नज़र में, ये लोग पूरी तरह गलत हैं।

इकॉनॉमिक पॉलिसी इन्स्टीट्यूट के डेटा का हवाला देते हुये, उन्होंने कहा था कि 2022 से 2023 के बीच, 30 शीर्षस्थ एच-वन बी नियोक्ताओं ने 85000 अमेरिकतन वर्कर्स का नौकरी से हटाकर, 34000 से अधिक गैस्ट वर्कर्स नौकरी पर रख लिये थे।

जब इंदिरा गांधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक महिला पत्रकार, जो एक मीटिंग कवर कर रही थीं, को वाशरुम जाने के लिये 24 अकबर रोड स्थित पुराने मुख्यालय भवन में जाना पड़ा।

नये मुख्यालय का काम-काज एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चल रहा है तथा उसका कार्यकर्ताओं और नेताओं से कोई सम्पर्क नहीं रहा है, जिनसे मिलकर कांग्रेस पार्टी बनी है।

ऐसे समय, जब पार्टी के लिए अपने दरवाजे खुले रखना तथा कार्यकर्ताओं और नेताओं को अंदर आने देना जरूरी है, पार्टी की चिन्तन प्रक्रिया इसके ठीक उलट चल रही है।

इस व्यवस्था के लिये कौन और क्यों जिम्मेदार है?

यह व्यवस्था न केवल घबराहट पैदा करने वाली है, बल्कि साजिशपूर्ण प्रतीत हो रही है। बहुत से नेता इस व्यवस्था तथा बदलाव का दोषारोपण महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल पर कर रहे हैं। लेकिन क्या वे यह सब राहुल गांधी की सहमति के बिना कर सकते हैं।

क्या राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को कुछ भी करने की छूट दे रखी है?

तथा इस पूरे व्यवस्था-परिवर्तन में प्रियंका गांधी की भूमिका क्या है?

वे बिना विभाग की महासचिव हैं, लेकिन नये मुख्यालय की हाउस कीपिंग में लगी रहती हैं।

क्या गांधी परिवार को इस बात की जानकारी है कि वह उसके अपने कार्यकर्ताओं से किस प्रकार दूर होते जा रहे हैं, या फिर उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है?

नेताओं में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि एआईसीसी में विभिन्न पदों पर बैठे नेता किस तरह से अपने पद सुरक्षित बनाये रखने में लगे हुये हैं तथा वे नहीं चाहते कि इन पदों तक अन्य लोग पहुँच सकें। बड़ी दिलचस्प, किन्तु घबराहट पैदा करने वाली स्थिति है।

पार्टी इस समय घोर असंतोष की जकड़ में है। नेतागण सवाल कर रहे हैं कि निर्णय किस तरह लिये जा रहे हैं तथा पार्टी लगातार चुनाव क्यों हारती जा रही है और इस स्थिति के बावजूद, सब कुछ व्यवस्थित और ठीक करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।

फ्रांस ने अच्छी तरह से अमेरिका को अंगूठा दिखाया और दादागिरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **दूसरी और अमेरिका अभी भी ज़ैलैंस्की द्वारा वाइट हाउस में की गई "धृष्टता" के लिये प्रतिशोध लेने की फिराक में है तथा यूक्रेन युद्ध की खुफिया जानकारियाँ साझा करने से इन्कार कर दिया है।**
- **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप व अमेरिका के बीच जो विश्वास व मित्रता का रिश्ता था, वो इतना बुरा छिन्न-भिन्न पहले कभी नहीं हुआ था। पर, अब क्या फ्रांस की नई भूमिका से अमेरिका यूरोप से एकदम कट सा नहीं गया।**

पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि परमाणु सुरक्षा और रक्षा कवच का विस्तार यूरोप के अन्य देशों तक करने के लिए रणनीतिक वार्ता शुरु की जानी चाहिए। यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन ही हैं, जिनके पास अन्य देशों, खासकर रूस, के हमले से बचने के लिए परमाणु हथियारों का भंडार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलैंस्की की ट्रम्प से हुई विनाशकारी मुलाकात के बाद लंदन में यूरोपियन देशों की बैठक बुलाई थी।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अमेरिका से अलग होकर यूक्रेन की शांति योजना पर स्वतंत्र रूप से काम करने की मांग ट्रंप के समक्ष चुनौती पेश कर दी है। यह योजना एक छोटे समूह द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें फ्रांस, यू.के., जर्मनी और पश्चिमी यूरोप के कई प्रमुख समूह शामिल हैं।

यह ट्रम्प के रूसियों से स्वतंत्र रूप से सम्पर्क साधने और यूक्रेन वॉर खत्म करने की कोशिश के एकदम उलट है। ट्रम्प ने अपनी मुहिम में किसी भी यूरोपियन देश को साथ नहीं लिया था। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब में रूस के प्रतिनिधियों से मिला था। इसमें यूरोपियन देश तो दूर यूक्रेन का भी प्रतिनिधित्व नहीं था।

ट्रम्प ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात किए बिना ही मिनरल डील भी घोषित कर दी थी। ट्रम्प एक दिन में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए यह सब कर रहे थे ताकि वे यह साबित कर सकें कि वे सुप्रीम डील मेकर हैं।

पर अमेरिकन्स के अक्खड़ रूख के कारण इन प्रयासों पर रोक लग गई हैं। अब फ्रांस ने इसका कूटनीतिक लाभ उठाकर अमेरिका से अलग अपना स्वतंत्र रूख घोषित कर दिया है। मैक्रों ने कहा है कि शांति होने तक यूरोपियन सैनिक यूक्रेन में ही डटे रहेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति को, आक्रमण के विरूद्ध लड़ने के अपने संकल्प को दिखाने के लिए यूरोपीय देश यूक्रेन और युद्ध में घिरे उसके राष्ट्रपति को और अधिक समर्थन दे रहे हैं। फ्रांस द्वारा उठाए गए कदम अमेरिका को शांति प्रक्रिया से और यूरोप के कूटनीतिक क्षेत्र से एक तरह से अलग-थलग कर रहे हैं।

हालांकि, फ्रांस के राष्ट्रपति कूटनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन, यह आसान नहीं होगा। अमेरिका, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ैलैंस्की को, वाइट हाउस में अमेरिका के खिलाफ बोलने की धृष्टता तथा आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करने के लिए सज़ा देने की अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ रहा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने के साथ-साथ खूफिया जानकारी भी साझा नहीं करने के आदेश दिए है। अमरीकी, बदला लेने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने उनकी हर बात मानने से इन्कार कर दिया। इसके कारण, रूस का प्रतिरोध करने की यूक्रेन की क्षमता सीमित हो गई है। इस बीच, रूस ने यूक्रेन के विरूद्ध अपनी आक्रामकता को बढ़ा दिया है तथा यूक्रेन पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है।

परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता दर्शाने के लिए और यूरोप के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए साहसी व निडर दांव खेला है। यह अमेरिका पर 1946, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जो भरोसा बना था और यूरोपियन देशों की निर्भरता बढ़ी थी, उसे छीन लेने जैसा है।

तमिलनाडु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करते हुये कहा कि उनकी सरकार अन्य भाषाओं का भी सम्मान करती है। "अगर आप अपनी भाषा को प्रेम और सम्मान देते हैं, तो आप अन्य भाषाओं के प्रति भी वैसा ही करें। मुझे यकीन है कि भैया जी मुझसे सहमत होंगे।"

जोशी के बयान पर आईं कड़ी प्रतिक्रियाओं के एक दिन बाद, भैया जी ने स्वयं "ऑन रिकार्ड" स्पष्टीकरण दिया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। "मराठी मेरी जन्मजात भाषा है तथा मुझे इस पर गर्व है। मराठी मुम्बई और महाराष्ट्र की भाषा है, इस बारे में दो राय नहीं हैं। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मुम्बई में मिलजुलकर रहते हैं।"

घाटकोपर के एक समारोह में, अपने भाषण के सम्बंध में भैया जी ने पुनः स्पष्टीकरण दिया: "मुम्बई में एक भाषा नहीं बोली जाती हैं। मुम्बई के प्रत्येक हिस्से में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। घाटकोपर क्षेत्र की भाषा गुजराती है। इसलिये, अगर आप मुम्बई में रह रहे हैं तो आपको मराठी सीखना जरुरी नहीं है।"

ठाकरे ने कहा कि भैयाजी का बयान मुम्बई को विभाजित करने के आरएसएस और भाजपा के छिपे हुये एजेंडा को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा, "मराठी मानुष" (सबका) स्वागत कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी उसे हानि पहुँचा सकता है।"

हज यात्रा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। ऐसे में नीतिगत विषय में कोर्ट द्वारा कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600